नवल टाइम्स

RNI No. UTTHIN/2012/42590

भारत सरकार से विज्ञापनों के लिए मान्यता प्राप्त

वर्ष : 14 अंक: 18 हिन्दी साप्ताहिक हरिद्वार, बृहस्पतिवार 22 मई 2025 मूल्य: 1 रूपया पृष्ठ: 4

एक देश एक चुनाव से और अधिक सशक्त होगा लोकतंत्र: मुख्यमंत्री

संयुक्त संसदीय समिति की बैठक में मुख्यमंत्री धामी ने किया प्रतिभाग

देहरादून (सू.वि.)। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को मसूरी रोड स्थित एक होटल में एक देश, एक चुनाव विषय पर संयुक्त संसदीय समिति के साथ संवाद कार्यक्रम में प्रतिभाग किया।

इस अवसर पर उन्होंने संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष पीपी चैधरी एवं समिति के सभी सदस्यगणों का स्वागत और अभिनंदन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि 'एक देश एक चुनाव' हमारे लोकतंत्र को और अधिक सशक्त, प्रभावी और समावेशी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।

उन्होंने कहा कि हमारी चुनाव प्रणाली विविधताओं के बावजूद प्रभावी और मजबूत रही है, लेकिन अलग-अलग समय में चुनाव होने से बार-बार आचार संहिता लगती है, इसके चलते राज्यो के सारे काम ठप पड़ जाते हैं। जब भी चुनाव आता है, तो बड़ी संख्या में कार्मिकों को मूल कार्य से हटाकर चुनाव ड्यूटी में लगाना पड़ता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले तीन सालों में राज्य में विधानसभा, लोकसभा और निकाय चुनावों की आचार संहिता के कारण 175 दिन तक राज्य की प्रशासनिक मशीनरी नीतिगत निर्णय लेने की प्रक्रिया से वंचित रही। छोटे और सीमित संसाधनों वाले राज्य के लिए ये 175 दिन शासन व्यवस्था की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि विधानसभा निर्वाचन का पूर्ण व्यय भार राज्य सरकार वहन करती है और लोकसभा निर्वाचन का व्यय भार केंद्र सरकार द्वारा उठाया जाता है। दोनों चुनाव एक साथ कराए जाएं तो राज्य और केंद्र सरकार पर व्यय भार समान रूप से आधा-आधा हो जाएगा। दोनों चुनाव एक साथ कराने से कुल व्यय में लगभग 30 से 35 प्रतिशत तक की बचत होगी। इसका उपयोग राज्य के स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, जल, कृषि एवं महिला सशक्तिकरण जैसे अनेक क्षेत्रों में किया जा सकता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड में जून से सितंबर का समय चारधाम यात्रा के साथ-साथ, बारिश का भी होता है, ऐसे में चुनावी कार्यक्रम होने से बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

इसके अलावा जनवरी से मार्च तक वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही के समय भी चुनावी प्रक्रिया निर्धारित नहीं की जानी चाहिए। फरवरी-मार्च के माह में हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट बोर्ड परीक्षाएं होने से प्रशासनिक संसाधनों पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड जैसे पहाड़ी और विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाले राज्यों में एक देश एक चुनाव महत्वपूर्ण है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड के दुर्गम क्षेत्रों में मतदान केंद्रों तक पहुंचना कठिन होता है, जिसके कारण चुनाव की प्रक्रिया में अधिक समय और संसाधन लगते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में मतदाताओं के लिए चुनाव में भाग लेना भी चुनौतीपूर्ण होता है, बार-बार चुनाव होने से लोगों में मतदान के प्रति रुझान कम होता है और मतदान प्रतिशत भी घटता है।

एसएसपी ने किया थाना पथरी का वार्षिक निरीक्षण

हरिद्वार(नवल टाइम्स)। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रमेन्द्र सिंह डोबाल ने थाना पथरी का वार्षिक निरीक्षण किया। सेरिमोनियल गार्द द्वारा सलामी के पश्चात शुरु हुए सालाना निरीक्षण में श्री डोबाल द्वारा थाना कार्यालय, मालखाना, कर्मचारी मैस, बैरक आदि की व्यवस्थाओं को परखने के साथ ही राजकीय अभिलेखों में अंकित प्रविष्ठियों को भी परखा जो भी खामियां पायी गयी, उन्हे क्षेत्रधिकारी लक्सर को अपने निकट पर्यवेक्षण में पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया। इस दौरान सफाई व्यवस्था एवं मुकदमें से संबंधित माल को सही दशा में रखने पर संतुष्टी व्यक्त करते हुए एसएसपी द्वारा अभिलेखों को अध्यावधिक करने, निर्णित मालों के शीघ्र निस्तारण के प्रयास करने सहित अपनी समस्या लेकर थाने आने वाले जनमानस की उचित मदद करने के निर्देश दिए गए। साथ ही उन्होंने क्राइम किट बॉक्स का कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने, थाना परिसर के खाली स्थानों पर हरे फलदार वृक्ष लगाने, पुराने फर्नीचर आदि सरकारी सामान जीपी लिस्ट के मुताबिक पुलिस लाइन में जमा कर नया सामान एवं जवानों के लिए बुलेट प्रफु जैकेट प्राप्त करने के भी निर्देश दिए गए। माल खाने में उत्तर प्रदेश के समय के काफी माल लंबित है। पुलिस अधीक्षक देहात को निर्देशित किया गया कि वह देहात क्षेत्र के एक सूची तैयार करें इसके निस्तारण की प्रक्रिया हेतु जनपद सहारनपुर से पत्राचार करें और लंबित माल का निस्तारण करवाकर अनुपालन से अवगत कराएंगे। थाना क्षेत्र में जो आदतन अपराधी है उनकी एचएस खोली जाये एंव उनकी नियमित निगरानी हेतु हल्का प्रभारियों को निर्देशित किया जाये, आम जनता की सुविधा हेतु थाना में जो लेण्ड़लाइन टेलीफोन लगाया गया है वह हर समय चालू दशा में होना चाहिए जिससे की कोई भी फरियादी अपनी समस्या को थाने मे किसी भी समय दर्ज करा सकता है। निरीक्षण पश्चात श्री डोबाल द्वारा पुलिस कर्मचारियों एवं ग्राम चैकिदारों का सम्मेलन लेते हुए उनकी समस्याओं का निस्तारण किया गया तथा विवेचकों से मुकदमों की जानकारी लेते हुए गुण दोष के आधार पर उनका निश्चित समयावधि के भीतर निस्तारण करने के निर्देश दिए गए। उक्त अवसर पर पुलिस अधीक्षक देहात, क्षेत्रधिकारी लक्सर, थानाध्यक्ष पथरी एंव अन्य पुलिस अधिकारी समेत कर्मचारीगण मौजूद रहे।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति परीक्षा पैटर्न लागू किए जाने की तैयारी की जाए: मुख्य सचिव

देहरादून (नवल टाइम्स)। मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने बुधवार को सचिवालय में शिक्षा विभाग की समीक्षा की। मुख्य सचिव ने विभाग के क्रियाकलापों पर अधिकारियों के साथ विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत परीक्षा पैटर्न एवं अन्य प्राविधानों को समाहित करने के लिए व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं।

भारत दर्शन योजना में इस वर्ष छात्रों की संख्या का लक्ष्य 1000, अगले वर्ष के लिए दिया 5000 का लक्ष्य

मुख्य सचिव ने माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत भारत दर्शन योजना को विस्तारित किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस वर्ष कम से कम 1 हजार बच्चों को भारत दर्शन यात्रा करायी जाए, जिसे अगले वर्ष बढ़ाकर 5000 करने का लक्ष्य रखा जाए। यह बच्चों के अन्वेषण एवं कौशल के लिए एक महत्त्वपूर्ण योजना है। उन्होंने भारत दर्शन यात्रा के दिवसों को बढ़ाकर 7 दिन किए जाने के भी निर्देश दिए। कहा कि भारत के प्रतिष्ठित विज्ञान एवं तकनीकी संस्थानों के साथ ही सैन्य प्रतिष्ठानों के भ्रमण कार्य आयोजित कराए जाएं।

क्लस्टर स्कूल भवनों के लिए डीपीआर एक माह में तैयार करने के दिए निर्देश

मुख्य सचिव ने प्रस्तावित 559 क्लस्टर विद्यालयों के निर्माण में तेजी लाए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने अगले एक माह में सभी चिन्हित क्लस्टर विद्यालय भवनों की डीपीआर तैयार कर प्रस्तुत किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने बैठक के दौरान ही फोन के माध्यम से शिक्षा विभाग द्वारा चयनित कार्यदायी संस्थाओं के विभागाध्यक्षों को एक माह में डीपीआर तैयार किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने स्मार्ट क्लासेज एवं कम्प्यूटर लैब निर्माण कार्यों की डीपीआर भी एक माह में तैयार किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्माण कार्यों में तेजी लाए जाने के लिए विभागीय निदेशकों को जिलाधिकारियों एवं कार्यदायी संस्थाओं से समन्वय के लिए जनपदों का दौरा किये जाने के निर्देश भी दिए। उन्होंने जनपदों के भ्रमण कार्यक्रमों के दौरान क्लस्टर स्कूलों में वाहन भाड़ा के लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता वाली जिला स्तरीय समितियों की बैठकें शीघ्र आयोजित कर ऐसे मामलों के निस्तारित किए जाने के भी निर्देश दिए।

प्रत्येक कार्य के लिए की जाए टाइम लाइन निर्धारित: मुख्य सचिव

मुख्य सचिव ने विद्यालयों के लिए सभी प्रस्तावित हॉस्टल फैसिलिटी की डीपीआर भी एक माह में तैयार किये जाने के निर्देश दिए। उन्होंने स्मार्ट क्लासेज हेतु कम्प्यूटर लैब के लिए एक समर्पित हैड खोले जाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्यों में देरी न हो इसके लिए प्रत्येक कार्य की समयसीमा निर्धारित की जाए, साथ ही सचिव, अपर सचिव एवं महानिदेशक स्तर पर लगातार कार्यों की समीक्षा की जाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश के भीतर आवासीय विद्यालयों को बढ़ाए जाने पर भी फोकस किया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि आवासीय विद्यालयों में एक वाहन उपलब्ध कराया जाए, ताकि मेडिकल इमरजेंसी एवं अन्य आपातकालीन परिस्थितियों में होने वाली समस्याओं से बचा जा सके। इस अवसर पर सचिव रविनाथ रमन एवं अपर सचिव रंजना राजगुरू सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

जंगली जनवरों को गर्मी से राहत दिलाने के लिए बनाये जा रहे जलाशय

हरिद्वार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिशा-निर्देशों पर जंगलों में वन अग्नि को रोकने के साथ-साथ वन्यजीवों के लिए पीने के पानी की कमी ना रहे, जिसको लेकर वन विभाग की ओर से एक ओर जहां हर रेंज में जलाशय बनाए जा रहे हैं, वही तालाबों को पुनर्जीवित किया जा रहा है, सबसे अधिक हाथी प्रभावित क्षेत्र में हर वक्त पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिए नलकूप लगाएं जा रहे हैं। हरिद्वार में गर्मियों के मौसम में बढ़ते तापमान के साथ-साथ गर्मी भी अत्यधिक बढ़ रही है। हरिद्वार के जंगलों में भीषण गर्मी में जंगली जानवरों को प्यास बुझाने के लिए दूर-दूर जाना पड़ता था, लेकिन अब हरिद्वार के घने जंगलों में जहां जंगली जानवरों का बसेरा हैं। राजाजी टाइगर रिजर्व की विभिन्न अलग-अलग रेंज, श्यामपुर, रसिया बर्ड, लाल डांग, पथरी, रानीपुर रेंज यह शहर से लगने वाला घना जंगल जहां जंगली जानवरों के लिए उनके पानी पीने के लिए हर संभव प्रयास विभाग कर रहा है उनके लिए जगह-जगह ट्यूबवेल से पानी आने की व्यवस्था की गई हैं, अब जंगल में ही हाथियों का झुंड, हिरण, तेंदुआ, बाग, या अन्य वन्य जीव अपनी प्यास आराम से बुझा सकेंगे।

सम्पादकीय

ऑनलाइन दुनिया में डूबते बच्चे

सोशल मीडिया से बच्चों और किशोरों का संबंध आज अभिभावकों के लिए सबसे अधिक चिंता का विषय बन चुका है। यह उन शीर्ष पांच मुद्दों में से एक है, जिन्हें माता-पिता क्लिनिक में, आपसी बातचीत में और विभिन्न सामाजिक-आर्थिक मंचों पर उठाते रहते हैं। माता-पिता तेजी से इस बात को लेकर जागरूक हो रहे हैं कि जब बच्चे ऑनलाइन दुनिया में डूबे होते हैं, तब वे असल जिंदगी से कितने कट जाते हैं, और फिर अभिभावकों को उन्हें इससे छुटकारा दिलवाने के लिए कैसा संघर्ष करना पड़ता है। अमरीका-स्थित एनजीओ सैपियन लैब्स की एक नई रिपोर्ट से यह पुष्टि हुई है कि माता-पिता की यह शंका सच है कि बच्चे के हाथ में पहली बार स्मार्टफोन या टैबलेट आने की उम्र और बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य के बीच सीधा संबंध है। जितनी कम उम्र में बच्चा यह उपकरण प्राप्त करता है, उसके मानसिक स्वास्थ्य में उतनी ही अधिक समस्याएं देखने को मिलती हैं। इस अध्ययन में बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य के सभी पहलुओं—आत्महत्या के विचार, दूसरों के प्रति आक्रामकता की भावना, वास्तविकता से अलग-थलग महसूस करना और मतिभ्रम पर विचार किया गया है। अध्ययन बताता है कि यदि स्मार्टफोन देर से दिया जाए तो इन समस्याओं में कमी आती है। लड़कियों और लडक़ों के आंकड़ों में अंतर चौंकाने वाला है। यदि किसी लडक़ी को छह साल की उम्र में स्मार्टफोन मिल गया तो 74 प्रतिशत मामलों में मानसिक समस्याएं देखी गईं। लेकिन अगर यही 18 साल की उम्र में दिया गया तो आंकड़ा घटकर 46 प्रतिशत रह गया। हालांकि यह अब भी बहुत अधिक है। लडक़ों में यह आंकड़ा 42 प्रतिशत से घटकर 36 प्रतिशत रहा। इसके पीछे कारण यह है कि लड़कियां सामाजिक स्वीकार्यता का दबाव लडक़ों की तुलना में अधिक महसूस करती हैं, जो उनके मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। बच्चे को स्मार्टफोन देना वैसा ही है, जैसे बिना ड्राइविंग लाइसेंस के किसी अनाड़ी बच्चे को तेज रफ्तार लैम्बॉर्गिनी थमा दी जाए। ऑनलाइन दुनिया में नेवीगेशन भी एक कौशल है, जो समय के साथ विकसित होता है। यह कौशल मस्तिष्क के विकास के कारण 20 की उम्र हो जाने पर ही पूरी तरह विकसित होता है। जब हम वयस्क ही इंस्टाग्राम 'रील्स' देखने के समय को कम करने के लिए जूझते हैं तो एक बढ़ते हुए मस्तिष्क वाले बच्चे के लिए यह कितना मुश्किल होगा।

पाक की आतंकवाद पर नीति

वैश्विक स्तरपर भारत को बौद्धिक क्षमता में सर्वश्रेष्ठ देश कहा जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है।क्योंकि कभी गुलामी की जंजीरों में जकड़ा भारत, आज के परिपेक्ष में विश्व के अनेक देशों में मूल भारतीय या तो राज कर रहे हैं या फिर बड़े पदों के माध्यम से राजकरण में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं, क्योंकि भारत के काम करने की रणनीति अलग ही है जो भारत की मिट्टी मैं समय हुई है। हथियारों से हमला करके तो एक झटके में किसी को भी समाप्त किया जा सकता है, परंतु दुनियाँ के सामने उसकी सच्चाई को उजागर कर, उसे तिल-तिल हर पल हर दिन अपमान में जीने पर मजबूर करता है, हम इस आर्टिकल के माध्यम से इस स्थिति को ऑपरेशन सच्चाई का नाम दे रहे हैं। अभी भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से सर्जिकल स्ट्राइक की सफ़लता को अंजाम दिया है, जिसमें हथियारों का उपयोग हुआ था।अब भारत के सर्वदलीय 7 प्रतिनिधि मंडलों जिसमें करीब सभी दलों के व अन्य सामान्य 59 प्रतिनिधि शामिल होंगे,जो दुनियाँ के कोने-कोने में जाकर मित्र देशों के पास, पाक की अंदरूनी सच्चाई बताकर उसे बेनकाब करेंगे,जिसे मैं इस आर्टिकल के माध्यम से ऑपरेशन सच्चाई का नाम दे रहा हूं। चूँकि पूरी दुनियाँ में आतंकवाद पर भारत का पक्ष रखने के लिए सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडलों को भेजना भारत की पारंपरिक जबरदस्त रणनीति लाजवाब है, इसलिए आज हम मीडिया में उपलब्ध जानकारी के सहयोग से इस आर्टिकल के माध्यम से,चर्चा करेंगे दुनियाँ में जाकर भारत का पक्ष रखेंगे सर्वदलीय सांसद सात,पाक़ को देंगे मात, आतंकवाद के प्रति पूरा विश्व होगा शून्य सहिष्णुता के साथ। बात अगर हम पाक के आतंकवाद के खिलाफ़ पूरी दुनियाँ में संदेश पहुंचाने की सरकार की रणनीति की करें तो, ऑपरेशन सिंदूर के बाद केंद्र सरकार की दुनियाँ में पाकिस्तान के आतंकवाद के खिलाफ़ संदेश पहुंचाने के लिए विश्व के अलग अलग देशों में अपना प्रतिनिधि मंडल भेज रही है। सांसदों के सात प्रतिनिधिमंडल दुनियाँभर के देशों में जाकर आतंकवाद के मुद्दे पर भारत का पक्ष रखेंगे और पाकिस्तान को घेरने की कोशिश करेंगे। वहीं, अब केंद्र सरकार ने सभी प्रतिनिधिमंडल में शामिल होने वाले सांसदों के नाम घोषिथ कर दिये हैं।हरएक प्रतिनिधि मंडल में सात से आठ सांसदों और कई राजनयिकों को शामिल किया गया है। हर प्रतिनिधिमंडल चार से पांच देशों का दौरा करेगा। संसदीय कार्य मंत्री ने अपने पोस्ट की शुरुआत, एक मिशन,एक संदेश, एक भारत से की। साथ ही उन्होंने सभी सांसदों और प्रतिनिधिमंडल में शामिल नेताओं की सूची भी साझा की। पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत सरकार आतंकवाद के खिलाफ अपने जीरो टॉलरेंस के संदेश को वैश्विक पटल पर मजबूती से रखने के लिए इस महीने के अंत में सात सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल को प्रमुख साझेदार देशों में भेजेगी। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा कि आतंक वाद के खिलाफ हमारे सामूहिक संकल्प को दर्शाते हुए,ऑपरेशन सिंदूर के तहत सात सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल जल्द ही प्रमुख देशों से मिलेंगे। बात कर हम मेरे दिए गए नाम ऑपरेशन सच्चाई के सात दलों के सदस्यों व उनके नेतृत्वकी करें तो (1) सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के पहले ग्रुप में सात सांसद भाजपा सांसद बैजयंत पांडा के नेतृत्व में सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन और अल्जीरिया जाएंगे।इस ग्रुप में भाजपा सांसद निशिकांत दुबे, एस फांगनोन कोन्याक, रेखा शर्मा, एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन औवैसी,सतनाम सिंह संधू, गुलाम नबी आजाद हैं। उनके साथ राजनियक हर्षवर्धन श्रृंगला जाएंगे। (2) सांसदों का दूसरा समूह भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व में यूके, फ्रांस, जर्मनी, यूरोप, इटली और डेनमार्क जाएगा। इसमें बीजेपी सांसद डी पुंडरेश्वरी, शिवसेना यूबीटी की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी, मनोनीत सांसद गुलाम अली खताना, कांग्रेस सांसद डॉ.अमर सिंह, भाजपा सांसद समिक भट्टाचार्य, एमजे अकबर होंगे।

भारत का पक्ष रखने की सराहनीय पहल

पहलगाम की क्रूर एवं बर्बर आतंकी घटना एवं उसके बाद भारत के सिंदूर ऑपरेशन में पाकिस्तान को करारी मात देने की घटना से निश्चित ही भारत की ताकत को दुनिया ने देखा। लेकिन इसके बाद पाक दुनिया से सहानुभूति बटोरने के लिये जहां विश्व समुदाय में अनेक भ्रम, भ्रांतिया एवं भारत की छवि को छिछालेदार करने में जुटा है, वहीं भारत का डर दिखा-दिखा कर ही पाक अनेक देशों से आर्थिक मदद मांग रहा है। इन्हीं स्थितियों को देखते हुए दुनिया के सामने भारत का पक्ष रखने के लिए केंद्र सरकार ने जिस तरह से सात सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडलों का गठन किया है, यह फैसला जितना सराहनीय है, उतना ही दुर्भाग्यपूर्ण एवं विडम्बनापूर्ण है इसका राजनीतिक विवादों में घिर जाना। यह राजनीति से ऊपर, मतभेदों से परे राष्ट्रीय एकता का एक शक्तिशाली प्रतिबिंब बनना चाहिए। देश की सुरक्षा, सैन्य उपक्रम, राष्ट्रीय एकता-अखण्डता एवं विदेश नीति से जुड़े विषय पर राजनीति होना, देश के हित में नहीं है।

पहलगाम हमले के बाद यह अफसोस की बात है कि पाकिस्तान का बचाव करने या उसके साथ मुखरता से खड़े होने वाले देशों या विश्व संगठनों के साथ-साथ भारतीय राजनीतिक दलों में विवाद का बढ़ना चिन्ताजनक है।। भारत के राजनीतिक दल प्रारंभ में एकजुट दिखें लेकिन राजनीतिक स्वार्थों के चलते अब उनमें कहीं-कहीं वैचारिक मतभेद उभर रहे हैं। पाकिस्तान दोषी होने के बावजूद पीड़ित होने का स्वांग रचकर सहानुभूति जुटाता रहा है। दुनिया के अनेक देश उसके झांसे में आ भी जाते हैं। ऐसे में, दुनिया के महत्वपूर्ण देशों में भारत का पक्ष रखने का मोदी सरकार का यह प्रयास बहुत जरूरी एवं दूरगामी सोच से जुड़स है। इस प्रयास को एक बड़े अभियान के रूप में लेना चाहिए। आतंकवाद के खिलाफ भारत की शून्य सहिष्णुता और ऑपरेशन सिंदूर का संदेश दुनिया तक पहुंचना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सभी दलों ने सरकार और सेना के प्रति समर्थन जताया था। सरकार ने भी उसी भावना का सम्मान करते हुए सभी दलों के सांसदों को प्रतिनिधिमंडल में शामिल किया है। कांग्रेस ने थरूर का नाम नहीं भेजा था, सरकार ने उन्हें अपनी तरफ से शामिल कर लिया। जिनके नाम कांग्रेस ने दिए थे, उनमें से सिर्फ आनंद शर्मा चुने गए।

शशि थरुर विदेश नीति के जानकार है। थरूर पहले संयुक्त राष्ट्रसंघ में काम कर चुके हैं, विदेश राज्यमंत्री रह चुके हैं। उनके अनुभव का फायदा निश्चित रूप से प्रतिनिधिमण्डल को मिलेगा, दुनिया में भारत का पक्ष सही परिप्रेक्ष्य में रखने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। हालांकि कांग्रेस को लगता है कि उसके सांसद को चुनने से पहले उससे पूछा जाना चाहिए था, इस अपेक्षा को गलत भी नहीं कहा जा सकता। मगर वर्तमान संवेदनशील हालातों में इसे विवाद का मुद्दा बनाने से बचा जा सकता था। लेकिन कांग्रेस के सदस्यों, खासकर सांसद शशि थरूर को लेकर हो रहा विवाद बिल्कुल अनचाहा एवं अनुचित है। इससे एक अच्छा एवं प्रासंगिक मकसद नकारात्मक खबरों में घिर गया है। भले ही शशि थरूर और कांग्रेस के रिश्ते पिछले कुछ समय से ठीक नहीं रहे हैं। लेकिन यह एक सांसद और उसकी पार्टी के बीच का मसला है। यहां जो मुद्दा सामने है, वह देश से जुड़ा है। इसमें सभी को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सोचना चाहिए।

युद्ध एवं आतंक जैसे हालातों में भारत ने अपना पक्ष रखने के लिए पहले भी समय-समय पर विपक्ष के शीर्ष नेताओं को आगे किया है और उसी परिपाटी को मोदी सरकार ने आगे बढ़ाकर देश की राजनीति व राजनय को मजबूती दी है। सात सदस्यीय बैजयंत जय पांडा, रविशंकर प्रसाद, शशि थरूर, संजय झा, श्रीकांत शिंदे, कनिमोझी करुणानिधि और सुप्रिया सुले के नेतृत्व में हमारे देश के नेता 32 देशों का दौरा करेंगे। यह विपक्ष के नेताओं के लिए भी स्वर्णिम अवसर है कि वह अपनी काबिलियत एवं देशहित को देश के सामने साबित करें। क्योंकि राष्ट्र एवं राष्ट्रीय एकता सबसे ऊपर है। बांटने वाली राजनीति से अलग जब हम देशहित के पक्ष में खड़े होंगे, तभी आतंकवाद से लड़ने में सहूलियत एवं सफलता मिलेगी। क्या दुनिया ने भारत के सीमित सैन्य अभियान के महत्व, संयम और समझदारी को ठीक से समझा है? क्या भारत आतंकवाद के खिलाफ संपूर्ण युद्ध नहीं छेड़ सकता था? अगर भारत ने युद्ध को नहीं बढ़ाया, तो इसका अर्थ कतई यह नहीं कि भारत का पक्ष कमजोर है। भारत चाहता तो पाक को हर मोर्चे पर नेस्तनाबूद कर सकता है, लेकिन भारत का लक्ष्य आतंकवाद को समाप्त करना है।

भारत ने पाकिस्तान और पीओके में बसे 9 आतंकी ठिकानों को रात के अंधेरे में तबाह कर दिया। इसके बाद भारत ने ठान लिया कि पूरी दुनिया के सामने आतंकवाद परस्त पाकिस्तान का चेहरा बेनकाब करना है, जिसकी जिम्मेदारी अनुभवी एवं विशेषज्ञ सात सांसदों को सौंप कर सरकार ने सूझबूझ एवं परिपक्व नेतृत्व का परिचय दिया है। सांसदों के सात प्रतिनिधिमंडल दुनियाभर के देशों में जाकर आतंकवाद के मुद्दे पर भारत का पक्ष रखेंगे। हर एक प्रतिनिधिमंडल में 6-7 सांसद और कई राजनयिक शामिल होंगे। भारत की शांति, अहिंसा, विकास एवं विश्व बंधुत्व का संदेश सात प्रतिनिधिमंडलों के जरिये दुनिया तक पहुंचना इसलिए भी जरूरी है कि भारत को तेज विकास करना है और अब वह पहलगाम जैसे किसी आतंकी हमले को बर्दाश्त नहीं कर सकता। गौर करने की बात है कि सात प्रतिनिधिमंडलों में 59 सदस्य शामिल किए गए हैं, जिनमें सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के 31 नेता और अन्य दलों के 20 नेता शामिल हैं। इस तरह सर्वदलीय सांसदों की टीमों को अंतरराष्ट्रीय कूटनीतिक मिशन पर भेजने से भारत का पक्ष मजबूत होगा, दुनिया में आतंक के विरुद्ध सकारात्मक वातावरण बनेगा। ये दौरे न सिर्फ आतंकवाद पर भारत की नीतियों को साफ करेंगे, बल्कि पाक की हरकतों को भी दुनिया के सामने बेनकाब करेंगे।

सात प्रतिनिधिमंडल में जिन नेताओं को नेतृत्व दिया गया है, उसमें भी अन्य दलों को प्राथमिकता देकर एक संतुलन एवं सूझबूझ का परिचय दिया गया है। आइडिया ऑफ इंडिया के साथ सुगठित इस टीम इंडिया के कंधे पर बड़ी एवं महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। दुनिया के निर्णायक नेताओं से मिलकर यह बताना जरूरी है कि आइडिया ऑफ पाकिस्तान और आइडिया ऑफ इंडिया के बीच कितनी चौड़ी खाई है, यह खाई संबंधित देशों ही नहीं, दुनिया को प्रभावित करने वाली है। दूसरे शब्दों में कहें, तो पाकिस्तान आतंकवादी मानसिकता से ग्रस्त है एवं आतंक को पोषित एवं पल्लवित करने वाला देश है। उसके आतंकवाद ने भारत ही नहीं, दुनिया के अनेक देशों को भारी नुकसान पहुंचाया है। एक देश, जो आतंक की बुनियाद पर खड़ा है, न उसे शर्म है, न पछतावा। वहां ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए आतंकियों व उनके परिजन को जैसा राजकीय सम्मान दिया गया है, जैसे पाक फौज आतंकी सरगनाओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी देखी गई है, उस तरफ से मुंह मोड़कर अगर दुनिया खड़ी होगी, तो यकीन मानिए, फिर इंसानियत का खून होगा और आतंकवाद को बल मिलेगा।

ऑपरेशन सिन्दूर भारत की बदलती रणनीति का हिस्सा बना है। भारत अब पहले की तरह केवल कूटनीतिक जवाब तक सीमित नहीं रहा, बल्कि वह सैन्य कार्रवाई के जरिए आतंकवाद के खिलाफ कड़ा संदेश भी देना जानता है। पाक सेना आतंकी संगठनों का इस्तेमाल करती है, लेकिन उसकी यह नीति न केवल भारत के लिए खतरा है, बल्कि पाक के आंतरिक स्थायित्व को भी कमजोर करती है। जब तक पाक सेना अपनी नीतियों में बदलाव नहीं करती तब तक इस तरह के आतंकी तनाव बार-बार सामने आएंगे। पाक भविष्य में फिर से भारत के खिलाफ आतंकी हमले कर सकता है क्योंकि यह उसकी रणनीति का हिस्सा है।

पाक सेना की आतंकवाद समर्थक नीतियां और भारत की आक्रामक जवाबी रणनीति इस क्षेत्र में स्थायी शांति की राह में बड़ी बाधाएं हैं। स्पष्ट होता है कि यह संघर्ष केवल दो देशों के बीच का विवाद नहीं है बल्कि इसमें पूरी दुनिया से जुड़े गहरे ऐतिहासिक, वैचारिक और रणनीतिक आयाम हैं। इसलिये दुनिया के बड़े राष्ट्र पाक की आतंकी सोच से परिचित हो, इसी सोच से दुनिया को परिचित कराना सात सदस्यीय प्रतिनिधि मण्डल का मिशन है।

जैव विविधता पृथ्वी पर सभी जीवन का आधार है

इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस का विषय है प्रकृति के साथ सामंजस्य और सतत विकास।प्राचीन समय से ही भारत के ऋषि-मुनियों को प्रकृति संरक्षण और मानव के स्वभाव की गहरी जानकारी थी। वे जानते थे कि मानव अपने क्षणिक लाभ के लिए कई मौकों पर गंभीर भूल कर सकता है। अपना ही भारी नुकसान कर सकता है। इसलिए उन्होंने प्रकृति के साथ मानव के संबंध विकसित कर दिए। ताकि मनुष्य को प्रकृति को गंभीर क्षति पहुंचाने से रोका जा सके।भारत में पेड़-पौधों, नदी-पर्वत, ग्रह-नक्षत्र, अग्नि-वायु सहित प्रकृति के विभिन्न रूपों के साथ मानवीय रिश्ते जोड़े गए हैं। पेड़ की तुलना संतान से की गई है तो नदी को मां स्वरूप माना गया है। जैव विविधता पृथ्वी पर सभी जीवन का आधार है और सभी लोगों के आर्थिक समृद्धि के लिए मौलिक है। पृथ्वी पर सबसे अधिक जैव विविधता वाले स्थानों में से कुछ पारिस्थितिकी तंत्रों की एक श्रृंखला है, जिनमें से प्रत्येक में समृद्ध वनस्पति और जीव हैं।इन जैव विविधता वाले हॉटस्पॉट में, अनगिनत प्रजातियां जटिल पारिस्थितिक तंत्र में सह-अस्तित्व में रहती हैं, जिनमें से प्रत्येक अपने संबंधित पारिस्थितिकी तंत्र के नाजुक संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। 1992 में रियो डी जेनेरियो में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन में जैव विविधता की मानक परिभाषा अपनाई गयी। इस परिभाषा के अनुसार, जैव विविधता के समस्त स्रोतों यथा- अंतर क्षेत्रीय, स्थलीय, सागरीय एवं अन्य जलीय नक्षत्रों के अनुसार जीवों के मध्य अंतर एवं साथ ही उन सभी स्रोत समूह, जहां ये भाग हैं, में पाई जाने वाली विभिन्नताएं हैं।भारत भी दुनिया के सबसे जैव विविधता वाले देशों में से एक है, जहां घने वर्षा वनों से लेकर तटीय आर्द्र भूमि तक समृद्ध पारिस्थितिकी तंत्र हैं। भारत दुनिया के शीर्ष 10 जैव विविधता वाले देशों की सूची में शामिल है।जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण, अति-दोहन और भूमि उपयोग परिवर्तन जैसी व्यापक समस्याएं जैव विविधता में गिरावट का कारण बन रही है।सुंदरबन जैसे मैंग्रोव वन समुद्र-स्तर में वृद्धि, कीचड़ की कमी और सिकुड़ते पर्यावासों जैसे 'तिहरे खतरे' का सामना कर रहे हैं। जंगलों में आग के कारण जंगल और जैवविविधता प्रभावित हो रही है।

केन्द्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने विगत 16 मई को काठमांडू में जलवायु परिवर्तन और पर्वतीय क्षेत्रों पर इसके प्रभाव पर एक वैश्विक संवाद सागरमाथा संवाद को संबोधित करते हुए हिमालय की बढ़ती पारिस्थितिकी अति संवेदनशीलता की ओर दिलाया, जो तेजी से ग्लेशियर पिघलने की ओर इशारा है। जलवायु संकट बढ़ाने में बहुत कम योगदान देने के बाबजूद हिमालयी समुदाय खतरे में है। हिमालय क्षेत्र में तापमान वृद्धि के कारण प्रजातियां अधिक ऊंचाई की ओर जा रही हैं, जिससे उच्च-तुंगता पर वास करने वाले हिम तेंदुए जैसे जीवों के लिये खतरा उत्पन्न हो रहा है।हिमालय पर्वतों से भी पूरानी पश्चिम घाट जो कि गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु से गुजरता है, जिसके संरक्षण के लिए भारत सरकार द्वारा 2011 में गाडगिल और 2013 में कस्तूरी रंगन समिति का गठन किया था। विशेषज्ञों ने सरकार को सुझाव दिया कि पश्चिम घाटों पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्रों के रूप में घोषित किया जाए।

उत्तराखण्ड शासन

देवभूमि रजत उत्सव

देवभूमि उत्तराखण्ड

श्री यमुनोत्री
30 अप्रैल, 2025

श्री गंगोत्री
30 अप्रैल, 2025

श्री केदारनाथ
2 मई, 2025

श्री बदरीनाथ
4 मई, 2025

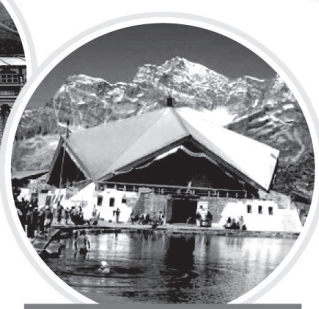

श्री हेमकुंट साहिब
25 मई, 2025

हरित चारधाम यात्रा

पुष्कर सिंह धामी
मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड

आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन

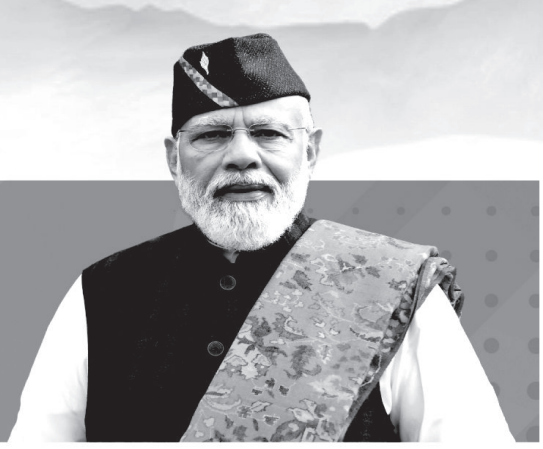

नरेन्द्र मोदी
प्रधानमंत्री

सुगम एवं सुरक्षित चारधाम यात्रा

चारधाम मार्ग के समीप आध्यात्मिक और प्राकृतिक रत्न

यमुनोत्री के पास: जानकी चट्टी, हनुमान चट्टी, खरसाली गांव, सप्तऋषि कुंड, पांडव गुफा, लाखा मण्डल, केदारकांठा ट्रैक, राणा चट्टी

गंगोत्री के पास: गौमुख ट्रैक, भोजबासा, तपोवन, सूर्यकुंड व गौरीकुंड, हर्षिल वैली, मुखीमठ (मुखबा), दयारा बुग्याल ट्रैक, गरतांग गली, काशी विश्वनाथ मन्दिर, नचिकेताताल, डौडीताल

केदारनाथ के पास: भैरवनाथ मन्दिर, वासुकीताल, गौरीकुंड, त्रियुगीनारायण मन्दिर, चोपता-तुंगनाथ-चंद्रशिला, गुप्तकाशी, देवरियाताल

बदरीनाथ के पास: माणा गांव, व्यास गुफा और गणेश गुफा, भीमशिला, औली, फूलों की घाटी, वसुधारा जलप्रपात, चरणपादुका, तप्तकुंड, नारदकुंड, ज्योतिर्मठ (जोशीमठ), सतोपंथ झील, पाण्डुकेश्वर, आदिबदरी मन्दिर, हेमकुंट साहिब

यात्रा के लिए जरुरी सामान

रेनकोट	सनग्लासेस	पानी की बोतल
मास्क	ग्लूकोस बिस्कुट	लाठी
कोल्ड क्रीम	टार्च	मंकी कैप
मफलर	कैनवास जूते	कैश
मोज़े	सैनिटाइज़र	स्वेटर
छाता	पहचान पत्र	दस्ताने

पंजीकरण के लिए

registrationandtouristcare.uk.gov.in

Toll Free number 0135 1364

Download the App:
touristcareuttarakhand

Google play | Download on the App Store

हेलीकॉप्टर/अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं

www.heliyatra.irctc.co.in

आईआरसीटीसी हेल्पलाइन नं 1800110139
080-44647998/080-35734998

उत्तराखण्ड पर्यटन टोल फ्री नंबर:
1364/0135 3520100

महत्वपूर्ण सूचना

- यात्रा से पूर्व पंजीकरण अवश्य करायें।
- रजिस्ट्रेशन में सही मोबाईल नम्बर दर्ज करें।
- धामों पर "दर्शन टोकन" अवश्य प्राप्त करें।
- यात्रा मार्ग पर विभिन्न पड़ावों पर विश्राम करते हुए प्रस्थान करें।
- यात्रा मार्गों पर गंदगी न फैलायें एवं मार्ग को स्वच्छ रखने में सहयोग करें।
- कृपया वाहनों की गति नियंत्रित रखें एवं वाहनों को निर्धारित स्थलों पर ही पार्क करें।
- greencard.uk.gov.in पर अपने वाहन का रजिस्ट्रेशन करवाएं।
- यात्रा के दौरान सिंगल यूज़ प्लास्टिक का प्रयोग न करें।

स्वास्थ्य का रखें खास ख्याल

- यात्रा आरंभ करने से पहले निकटतम स्वास्थ्य केंद्र में अपनी जांच अवश्य करायें।
- जिन्हें हृदय संबंधी दिक्कतें तथा हाइपरटेंशन है, वे अतिरिक्त सावधान रहें।
- रास्ते में कहीं भी लगे कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो आगे यात्रा न करें और नजदीकी चिकित्सा केंद्र से संपर्क करें।
- जरुरी दवाइयां, फर्स्ट ऐड किट एवं मेडिकल हिस्ट्री सम्बन्धी रिपोर्ट साथ लेकर चलें।

आपकी यात्रा मंगलमय हो

त्रियुगी नारायण मन्दिर | गरतांग गली | फूलों की घाटी | हर्षिल वैली | देवप्रयाग | ऋषिकेश | औली

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा जनहित में जारी | www.uttarainformation.gov.in | uttarakhandDIPR | DIPR_UK | uttarakhand DIPR

#ExploreUttarakhand
@DIPR_UK

बॉर्डर 2 के सेट पर सनी देओल से मिले उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद के सीईओ बंशीधर तिवारी

देहरादून(नवल टाइम्स)। उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बंशीधर तिवारी ने मंगलवार को देहरादून के हल्दूवाला स्थित बॉर्डर 2 के सेट पर सुप्रसिद्ध अभिनेता सनी देओल और निर्देशक अनुराग सिंह से मुलाकात की।

इस अवसर पर उनके साथ परिषद के संयुक्त सीईओ डॉ. नितिन उपाध्याय भी मौजूद थे। मुलाक़ात के दौरान उत्तराखंड की फिल्म नीति, लोकेशन विविधता और राज्य सरकार की ओर से दिए जा रहे समर्थन पर सार्थक चर्चा हुई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में बनी उत्तराखंड की वर्तमान फिल्म नीति को देश की सबसे प्रगतिशील नीतियों में एक माना जा रहा है, जहां फिल्म निर्माताओं को समय से शूटिंग की अनुमति, प्रशासनिक सहयोग और स्थानीय संसाधनों की सहज उपलब्धता मिलती है। श्री तिवारी ने बताया कि यहां फिल्म यूनिट को जिस तरह का सकारात्मक और सहज वातावरण मिल रहा है, वह प्रदेश को फिल्म निर्माण की दृष्टि से एक सशक्त गंतव्य बनाता है। सनी देओल भी इस दौरान काफी सहज और उत्साहित नज़र आए।

बॉर्डर 2 की बात करें तो यह फिल्म जेपी दत्ता, निधि दत्ता और टी-सीरीज़ के प्रोडक्शन में बन रही है, जिसकी शूटिंग फरवरी से देहरादून में चल रही है। केसरी फेम अनुराग सिंह इसके निर्देशक हैं और इसमें सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी जैसे प्रमुख कलाकार शामिल हैं। फ़िल्म के प्रोड्यूसर बिनोय गांधी ने बताया कि फिल्म 1971 के भारत-पाक युद्ध पर आधारित है और इसके लिए देहरादून के हल्दूवाला क्षेत्र में कश्मीर के एक गांव का भव्य सेट बनाया गया है। सेट निर्माण की शुरुआत पिछले साल नवंबर में हुई थी। फिल्म में युद्ध के सीन, टैंक और सेना के मूवमेंट जैसे दृश्य शामिल हैं और इसका विजुअल प्रजेंटेशन टथ् के लिहाज़ से भी बेहद महत्वपूर्ण है। फिल्म के आर्ट डायरेक्टर मयूर शर्मा हैं और एक्शन डायरेक्शन की जिम्मेदारी रवि वर्मा निभा रहे हैं, जो पहले जाट जैसी फिल्मों में भी अपने काम के लिए सराहे जा चुके हैं। इस प्रोजेक्ट से रोज़ाना लगभग 350 स्थानीय लोगों को काम मिल रहा है। फिल्म बॉर्डर 2 के अलावा इस समय उत्तराखंड में कई प्रमुख फिल्मों की शूटिंग चल रही है। तनु वेड्स मनु फेम निर्माता विनोद बच्चन की फिल्म गिन्नी वेड्स सनी 2 की शूटिंग देहरादून में हो रही है, जिसमें अविनाश तिवारी और 12वीं फेल फेम एक्ट्रेस मेधा शंकर मुख्य भूमिकाओं में हैं। इनके साथ गोविंद नामदेव और सुधीर पांडे जैसे अनुभवी कलाकार भी फिल्म का हिस्सा हैं। वहीं, अन्नू कपूर, पवन मल्होत्रा और बिजेंद्र काला अभिनीत कॉमेडी सटायर 'उत्तर दा पुत्तर' की शूटिंग देहरादून और ऋषिकेश में चल रही है।

उत्तराखंडी सिनेमा को प्रोत्साहन देने के तहत इन दिनों गढ़वाली भाषा की तीन फिल्मेंकृमारचा, तेरी माया और नमककृकी शूटिंग क्रमशः देहरादून, टिहरी और उत्तरकाशी में हो रही है। राज्य सरकार की पहल से इन फिल्मों को स्थानीय लोकसंस्कृति, परंपरा और बोली के साथ तकनीकी संसाधनों का भी भरपूर समर्थन मिल रहा है, जिससे क्षेत्रीय सिनेमा को एक नई दिशा और पहचान मिल रही है। वहीं, बीते कुछ समय में उत्तराखंड में कई उल्लेखनीय हिंदी फिल्मों और वेब सीरीज की शूटिंग पूरी हो चुकी है, जिनमें 'विकी विद्या का वो वाला वीडियो', 'तिकड़म', 'दो पत्ती', 'पुतुल', 'रौतू का राज', 'तन्वी द ग्रेट', 'पास्ट टेंस', 'केसरी 2' और 'मेरे हसबैंड की बीवी' प्रमुख हैं। वर्ष 2024 -25 में उत्तराखंड सरकार द्वारा 225 शूटिंग अनुमतियाँ जारी की गई। उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद लगातार राज्य को एक आकर्षक फिल्म निर्माण गंतव्य के रूप में स्थापित करने की दिशा में प्रयासरत है, जहां संस्कृति, प्रकृति, तकनीक और प्रशासनिक सहयोग का संगम फिल्म निर्माताओं को विशेष अनुभव प्रदान करता है।

पूर्व प्रधानमंत्री स्व. राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर दी कांग्रेसियों ने श्रद्धांजलि

हरिद्वार। महानगर कांग्रेस कमेटी हरिद्वार द्वारा देवपुरा चैक स्थित पं. गोविंद वल्लभ पंत पार्क में पूर्व प्रधानमंत्री स्व. राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गयी। इस अवसर पर महानगर कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष अमन गर्ग और स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारी प्रकोष्ठ अध्यक्ष मुरली मनोहर ने कहा राजीव गांधी भारत के सूचना क्रांति के नायक के साथ ही पंचायती राज के जनक थे। जिन्होंने लोकतंत्र को मजबूत करने का काम किया, उनके बलिदान से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए कि उनके दिखाए मार्ग पर चलकर देश को एकजुट रखने के लिए हमें संकल्प लेना चाहिए, यही उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि होग। पूर्व विधायक रामयश सिंह और वरिष्ठ नेता महेश प्रताप राणा ने कहा कि राजीव जी को सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम उनके दिखाए सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलें। वरिष्ठ नेता अशोक शर्मा और वरिष्ठ नेता मनोज सैनी ने कहा कि राजीव गांधी को सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम उनके दिखाएं मार्ग पर चलकर देश की एकता, अखण्डता को सांप्रदायिक ताकतों से लड़कर बचाने का काम करेंगे। यूथ कांग्रेस अध्यक्ष तुषार कपिल और

महिला कांग्रेस अध्यक्ष लता जोशी ने कहा कि स्व. राजीव की पुण्यतिथि पर हम यह संकल्प लें कि केंद्र सरकार द्वारा झूठ के प्रोपेगंडा के आधार पर प्रसारित नफरत को मोहब्बत से हरायेंगे। पार्षद विवेक भूषण विक्की और हिमांशु गुप्ता ने कहा कि राजीव गांधी ने अपने लहू से भारत वर्ष की सेवा की और अपने प्राणों का बलिदान तक कर दिया। इस अवसर पर हम उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं। महानगर कांग्रेस महासचिव तरूण व्यास और वरिष्ठ नेता बीएस तेजियान ने कहा कि राजीव गांधी जी ने मतदाता की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की यह भी एक ऐतिहासिक कदम रहा है। वरिष्ठ नेता राजेंद्र चुटैला और पार्षद प्रतिनिधि पुनीत कुमार ने कहा कि राजीव गांधी जी का जीवन हमें प्रेरणा देता है कि कैसे अपने प्राणों का बलिदान कर देश की सेवा को समर्पित किया। श्रद्धांजलि सभा में मुख्य रूप से ब्लॉक अध्यक्ष विकास चंद्रा, पार्षद प्रतिनिधि अकरम अंसारी, श्रमिक नेता विकास सिंह, ग्रेस कश्यप, बलराम गिरी कड़क, मुकुल जोशी, प्रदीप त्यागी, अशोक गुप्ता,यूथ कांग्रेस महासचिव शुभम जोशी, अरूण राघव, प्रदीप कुमार, मनोज जाटव, महेश बर्मन, अरूण चैहान, पीसीसी सदस्य राहुल चैधरी, आशीष प्रधान, कपिल पाराशर, आशु श्रीवास्तव, यश शर्मा, मनन अरोड़ा, दीपक पाण्डेय, कामेश्वर यादव, मंजू गोस्वामी, रंजना, हरीश अरोड़ा आदि कांग्रेस जन उपस्थित रहे।

रीप परियोजना की वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट पर एक दिवसीय कार्यशाला संपन्न

हरिद्वार (नवल टाइम्स)। मुख्य विकास अधिकारी के निर्देशन में आज विकास भवन रोशनाबाद स्थित सभागार में ग्रामोत्थान (रीप) परियोजना की वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट पर आधारित एक दिवसीय महत्वपूर्ण कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला की अध्यक्षता जिला परियोजना प्रबंधक संजय सक्सेना द्वारा की गई बैठक में वित्तीय वर्ष 2022-23, 2023-24 एवं 2024-25 के दौरान परियोजना के अंतर्गत संचालित गतिविधियों की गहन समीक्षा की गई। लक्षित कार्यों के प्राप्त आउटपुट और आउटकम पर विस्तृत चर्चा करते हुए कार्यान्वयन की गुणवत्ता को और बेहतर बनाने पर जोर दिया गया। बैठक का मुख्य फोकस आगामी वित्तीय वर्ष 2025-26 के लक्ष्यों का निर्धारण, वितरण और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर रहा।

मधुमक्खी पालन गतिविधि पर विशेष रूप से चर्चा की गई, जिसे ग्रामीण आजीविका सृजन के एक प्रभावी माध्यम के रूप में विकसित किया जा रहा है। इस गतिविधि की वर्तमान स्थिति, विस्तार की संभावनाएं और क्षेत्रीय स्तर पर इसके प्रभाव को लेकर विस्तृत संवाद हुआ।

इसके अतिरिक्त, विभिन्न गतिविधियों के सुचारू संचालन हेतु स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, निगरानी प्रणाली एवं कार्यान्वयन रणनीतियों पर भी विचार-विमर्श किया गया। सभी सहभागी स्टाफको कार्यों के निष्पादन में गुणवत्ता एवं समयबद्धता बनाए रखने हेतु आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान किया गया।

इस अवसर पर परियोजना निदेशक, डीआरडीए केएन तिवारी ने भी बैठक में भाग लिया और चल रही गतिविधियों की समीक्षा करते हुए उपयोगी सुझाव एवं दिशा-निर्देश दिए। जिला परियोजना प्रबंधक संजय सक्सेना द्वारा उन्हें परियोजना की प्रगति, उपलब्धियों एवं आगामी योजनाओं की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की गई, जिस पर उन्होंने संतोष व्यक्त किया।

कानूनी सलाहकार
एड. अनुज कुमार शर्मा
चैम्बर नं. 20, रोशनाबाद
हरिद्वार (उत्तराखंड)
मो. 9837387718

गगनयान की तैयारी से भारत आत्मनिर्भर और अग्रणी अंतरिक्ष राष्ट्र की ओर अग्रसर: त्रिवेन्द्र

हरिद्वार। हरिद्वार सांसद और उत्तराखंड के पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन संसदीय समिति के अपने चार दिवसीय अध्ययन दौरे के दौरान आंध्र प्रदेश में चेन्नई, श्रीहरिकोटा और तिरुपति का भ्रमण किया। उन्होंने वहां विभिन्न क्षेत्रों में पर्यावरणीय, वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकीय प्रगति और चुनौतियों का अवलोकन एवं मूल्यांकन किया। इस दौरान उन्हें श्रीहरिकोटा में पीएसएलवी 61 के प्रक्षेपण का प्रत्यक्ष अवलोकन का भी किया। उन्होंने इस दौरान सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र और अंतरिक्ष विभाग के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की। उन्होंने कहा कि चंद्रयान-3, आदित्य एल 1 जैसे मिशनों की सफल लॉन्चिंग और गगनयान की तैयारी भारत को आत्मनिर्भर

और अग्रणी अंतरिक्ष राष्ट्र बनाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। इस अध्ययन दौरे को लेकर उन्होंने कहा कि विज्ञान, पर्यावरण और सीएसआर के क्षेत्र में सहयोग, नीति और अनुसंधान की दिशा में महत्वपूर्ण संवाद और जमीनी निरीक्षण का अवसर प्रदान करता है, जिससे नीति निर्धारण में ठोस तथ्य आधारित सुझाव देने में सहायता मिलेगी।

स्वामी, मुद्रक व प्रकाशक संजीव शर्मा ने किरण ऑफसेट प्रिंटिंग प्रेस, निकट गुरूकुल कांगड़ी फार्मेसी, कनखल, हरिद्वार (उत्तराखंड) से छपवाकर, म.नं. डी-31/2 आदर्शनगर कालोनी, गोल गुरुद्वारा, सेंटमेरी स्कूल के पीछे, ज्वालापुर हरिद्वार (उत्तराखंड) से प्रकाशित किया।

: सम्पादक :
संजीव शर्मा
मो. 8057605991/9897106991
ईमेल: navaltimes@gmail.com
सभी विवादों का न्याय क्षेत्र हरिद्वार होगा

प्रबंध संपादक
डा. संदीप भारद्वाज
बिजनौर प्रभारी
विशाल शर्मा
सभी पद अवैतनिक हैं